

गलवान संघर्ष (2020) और भारत-चीन संबंधों पर उसका प्रभाव: एक राजनीतिक-वैज्ञानिक विश्लेषण

लेखक: आरती

सुपरवाइज़र: डॉ. सुनील कुमार जांगीड़

संबद्धता: रिसर्च स्कॉलर राजनीतिक शास्त्र, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर

सार (Abstract)

जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ ने भारत-चीन संबंधों में एक निर्णायक मोड़ उत्पन्न किया। यह 1975 के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर पहला जानलेवा संघर्ष था, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई और चीनी पक्ष को भी उल्लेखनीय क्षति पहुँची। इस घटना ने न केवल द्विपक्षीय सैन्य और कूटनीतिक समीकरणों को बदला, बल्कि आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, घरेलू राजनीति और जनमत स्तर पर भी गहरे असर डाले।

यह लेख राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से गलवान संघर्ष (2020) की पृष्ठभूमि, उसके तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों तथा भारत-चीन संबंधों में उभरते "नए सामान्य" (New Normal) की विवेचना करता है। अध्ययन में यथार्थवाद (Realism), सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma) और सॉफ्ट बैलेंसिंग (Soft Balancing) जैसी अवधारणाओं के माध्यम से सैन्य तैनाती, कूटनीतिक वार्ताओं, आर्थिक नीति-परिवर्तनों और भारत की बहुपक्षीय/क्षेत्रीय रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः, गलवान संघर्ष ने यह स्पष्ट किया कि सीमा-विवाद अब भारत-चीन संबंधों की परिधि में नहीं, बल्कि केन्द्र में आ चुका है, और जब तक LAC पर स्थिरता बहाल नहीं होती, तब तक दोनों देशों के बीच "सामान्य" संबंधों की पुनर्स्थापना सीमित और सशर्त रहेगी।

कुंजी-शब्द: गलवान घाटी, भारत-चीन संबंध, LAC, सीमाविवाद, सुरक्षा दुविधा, सॉफ्ट बैलेंसिंग, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक विज्ञान

1. भूमिका

भारत और चीन एशिया की दो प्रमुख उभरती शक्तियाँ हैं, जिनके बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी, अस्पष्ट और विवादित सीमा रेखा—लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC)—स्थित है। ऐतिहासिक रूप से 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों ने चरणबद्ध रूप से विश्वास निर्माण उपाय (Confidence Building Measures - CBMs) विकसित किए, जिनमें सीमा पर हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, फ्लैग-मीटिंग, और नियमित सैन्य संवाद शामिल थे। 2017 के डोकलाम गतिरोध के बावजूद, 2018 के वुहान और 2019 के मामल्लपुरम अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों के बाद यह धारणा बनी कि दोनों देश "प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग" (competition with cooperation) का संतुलन साध रहे हैं।

लेकिन अप्रैल-जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य जमावड़े और गलवान घाटी में घातक संघर्ष ने इस धारणा को झटका दिया। यह घटना केवल एक टैक्टिकल सैन्य टकराव नहीं थी, बल्कि उसने भारत की चीन-नीति, क्षेत्रीय साझेदारियों, आर्थिक संबंधों और घरेलू राजनीतिक विमर्श को गहराई से प्रभावित किया। यही कारण है कि गलवान संघर्ष राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से भारत-चीन संबंधों के अध्ययन में एक "वाटरशेड मोमेंट" (watershed moment) के रूप में देखा जा रहा है।

इस विषय पर अनेक विद्वानों ने भारत-चीन सीमा विवाद और गलवान संघर्ष के रणनीतिक प्रभावों का अध्ययन किया है। टेलिस (Tellis, 2020) ने पूर्वी लद्दाख संकट को चीन की व्यापक सामरिक प्रतिस्पर्धा की रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसमें सीमा-तनाव को शक्ति-संतुलन के साधन के रूप में उपयोग किया गया। फ्रेवल (Fravel, 2011) और गार्वर (Garver, 2016) ने चीन की नीति में आए बदलावों को सीनो-अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझाया है, जबकि मिलर (Miller, 2021) और मदन (Madan, 2020) ने इसे भारत की रणनीतिक पुनर्संतुलन (strategic recalibration) की प्रक्रिया का हिस्सा माना है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य गलवान संघर्ष के बहुआयामी प्रभावों—सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक, और घरेलू राजनीतिक—का व्यवस्थित विश्लेषण करना तथा भारत-चीन संबंधों में उभर रहे "नए सामान्य" की विशेषताओं को रेखांकित करना है। यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी और नव-यथार्थवादी ढाँचों के साथ-साथ सॉफ्ट बैलेंसिंग की अवधारणा का उपयोग करते हुए नीतिगत निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

2. शोध प्रश्न, उद्देश्य एवं पद्धति

2.1 मुख्य शोध प्रश्न

गलवान संघर्ष (2020) ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक और घरेलू-राजनीतिक आयामों को किस प्रकार बदला, और इसके परिणामस्वरूप उभरते "नए सामान्य" की विशेषताएँ क्या हैं?

2.2 शोध उद्देश्य

1. गलवान संघर्ष की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम का संक्षिप्त पुनर्निर्माण करना।
2. संघर्ष के बाद सीमा प्रबंधन और सैन्य तैनाती में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. भारत-चीन कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर पड़े प्रभावों की समीक्षा करना।
4. भारत की विदेश-नीति (विशेषकर इंडो-पैसिफिक, QUAD, मिनी-लेट्रल पहल) पर गलवान के प्रभाव को समझना।
5. घरेलू राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श और जनमत में आये बदलाव को रेखांकित करना।

2.3 शोध पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित गुणात्मक विश्लेषण (Qualitative Analysis) है। समाचार-रिपोर्ट, सरकारी वक्तव्य, नीति-पत्र, थिंक-टैंक रिपोर्ट और अकादमिक लेखों का उपयोग कर घटना-क्रम और नीति-परिवर्तनों की व्याख्या की गई है। विश्लेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी (Realist) और नियो-यथार्थवादी (Neo-Realist) ढाँचे तथा सॉफ्ट बैलेंसिंग (Soft Balancing) की अवधारणा को अपनाया गया है।

3. पृष्ठभूमि: भारत-चीन संबंध 1962 से 2019 तक

3.1 1962 का युद्ध और शीत युद्ध काल

1962 के भारत-चीन युद्ध ने दोनों देशों के बीच गहरी दरार उत्पन्न की। सीमा-विवाद का समाधान न होने के कारण LAC एक अस्पष्ट और विवादित रेखा बनी रही। शीत युद्ध के दौरान चीन का पाकिस्तान के साथ सामरिक गठबंधन भारत के लिए चिंता का विषय रहा। इस काल में द्विपक्षीय संवाद न्यूनतम था और सीमा पर छोटे-मोटे झड़प होते रहे।

3.2 आर्थिक उदारीकरण और संबंधों की बहाली (1988-2010)

1988 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की बीजिंग यात्रा के बाद उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद बहाल हुआ। 1993, 1996, 2005 और 2013 के सीमा-समझौते क्रमशः LAC पर शांति बहाली के लिए रूपरेखा प्रदान करते रहे। इन समझौतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे:

- LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखना

- सैन्य बलों का न्यूनतम उपयोग
- हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध
- नियमित बैठकों और विश्वास निर्माण उपायों का विकास

आर्थिक मोर्चे पर, 1990 के दशक के अंत से लेकर 2010 के दशक तक भारत-चीन व्यापार तीव्र गति से बढ़ा और चीन भारत का सबसे बड़ा सामान-व्यापार साझेदार बन गया। 2000 में मात्र 2.9 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार 2019 तक लगभग 92 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। फिर भी, बड़ी व्यापार असमानता (भारत के पक्ष में नकारात्मक), सीमा-विवाद, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण सामरिक अविश्वास बना रहा।

3.3 डोकलाम गतिरोध (2017) और अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

2017 का डोकलाम (भूटान सीमा पर) गतिरोध 73 दिनों तक चला और दोनों सेनाओं के बीच तनाव का एक प्रमुख उदाहरण था। हालाँकि इस गतिरोध का कूटनीतिक समाधान हुआ, लेकिन इसने यह स्पष्ट कर दिया कि LAC और सीमा-मुद्दे अत्यंत संवेदनशील हैं।

डोकलाम के बाद, 2018 में वुहान और 2019 में मामल्लपुरम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुए। इन बैठकों का उद्देश्य "रणनीतिक संचार" को मजबूत करना और सीमा-विवादों को "प्रबंधित" करना था। इससे यह धारणा बनी कि दोनों देश "प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग" का मार्ग अपना रहे हैं।

3.4 2020 से पूर्व की स्थिति

2019 तक भारत-चीन संबंध एक नाजुक संतुलन पर टिके थे। एक ओर आर्थिक सहयोग बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर सीमा पर सैन्य गतिविधियाँ, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और पेट्रोलिंग के दौरान "फेस-ऑफ" की घटनाएँ जारी थीं। इसी पृष्ठभूमि में 2020 का गलवान संघर्ष एक अप्रत्याशित लेकिन गहरा आघात बनकर सामने आया।

4. गलवान संघर्ष 2020: घटनाक्रम और तात्कालिक परिणाम

4.1 संघर्ष की पृष्ठभूमि (अप्रैल-मई 2020)

अप्रैल-मई 2020 से पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों—पेंगोंग त्सो (Pangong Tso), गलवान (Galwan), हॉट स्प्रिंग्स (Hot Springs), गोगरा (Gogra), देपसांग (Depsang) आदि—में चीनी सेना (PLA) ने असामान्य पैमाने पर सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती शुरू की। भारत के अनुसार, यह गतिविधियाँ पूर्व-स्थापित समझौतों और सीमा-प्रोटोकॉल का उल्लंघन थीं और इनका उद्देश्य LAC की यथास्थिति (status quo) को एकतरफा बदलना था।

क्षेत्र	गतिविधि विवरण
पेंगोंग त्सो	उत्तरी और दक्षिणी तट पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा
गलवान घाटी	पेट्रोल प्वाइंट 14 के पास चीनी तंबू और संरचनाएँ
हॉट स्प्रिंग्स	LAC के भारतीय पक्ष में चीनी सैनिकों की घुसपैठ
गोगरा	बफर जोन में चीनी उपस्थिति
देपसांग	पारंपरिक पेट्रोलिंग क्षेत्रों में प्रवेश अवरोध

Table 1: पूर्वी लद्दाख में अप्रैल-मई 2020 की चीनी सैन्य गतिविधियाँ

4.2 15-16 जून 2020: घातक मुठभेड़

15-16 जून 2020 की रात गलवान घाटी के पेट्रोलिंग प्वाइंट-14 (PP-14) पर दोनों सेनाओं के बीच घातक मुठभेड़ हुई। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिनमें कर्नल संतोष बाबू (कमांडिंग ऑफिसर, 16 बिहार रेजिमेंट) शामिल थे। चीन ने आधिकारिक रूप से 4 सैनिकों की मौत स्वीकार की, जबकि कुछ स्वतंत्र विश्लेषणों के अनुसार चीनी हताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि 1996 के समझौते के अनुसार LAC पर आग्नेयास्त्रों (firearms) के उपयोग पर प्रतिबंध था, इसलिए संघर्ष "निहत्थे" लेकिन अत्यंत हिंसक शारीरिक झड़पों, लोहे की छड़ों, कीलों वाले डंडों और पत्थरों के प्रयोग के साथ हुआ [2][8]। कड़ाके की ठंड (-10°C से कम तापमान) और ऊँचाई (लगभग 14,000 फीट) ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया।

4.3 तात्कालिक परिणाम और प्रतिक्रियाएँ

- **सैन्य स्तर:** भारत ने पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर सैनिक, टैंकों, तोपखाने और वायु शक्ति की अतिरिक्त तैनाती की [3][5]। LAC के दोनों ओर "फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट" की स्थिति बन गई, जिसमें दोनों सेनाएँ सर्दियों में भी तैनात रहीं—जो पहले असामान्य था।
- **राजनीतिक स्तर:** भारत सरकार ने चीन को कड़ा संदेश दिया कि LAC पर यथास्थिति बदलने के प्रयास स्वीकार्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "भारत किसी को भी अपनी सीमा में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं देगा"।
- **कूटनीतिक स्तर:** विदेश मंत्रालय और सैन्य अधिकारियों के बीच तीव्र संवाद शुरू हुआ। कोर कमांडर स्तर की बैठकें (Corps Commander-level talks) नियमित रूप से आयोजित होने लगीं।
- **जनमत स्तर:** भारत में चीन-विरोधी भावनाएँ तीव्र हो गईं। सोशल मीडिया पर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग, शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि और राष्ट्रवादी विमर्श का उभार देखा गया।

गलवान संघर्ष "सुरक्षा दुविधा" (Security Dilemma) का क्लासिक उदाहरण है, जिसमें एक पक्ष की रक्षात्मक तैनाती दूसरे पक्ष ने आक्रामक मानी और पारस्परिक अविश्वास का चक्र गहराता गया। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार, ऐसी स्थिति में राज्य अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं और सैन्य शक्ति को प्रमुख साधन के रूप में देखते हैं।

5. सैन्य-रणनीतिक प्रभाव: LAC पर "स्थायी तनाव" और चरणबद्ध डिसएंगेजमेंट

5.1 कोर कमांडर स्तर की वार्ताएँ

गलवान के बाद भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की कई दौर की वार्ताएँ हुईं। 2020 से 2025 तक 20 से अधिक राउंड की बैठकें संपन्न हुईं, जिनका उद्देश्य सीमा पर तनाव कम करना और डिसएंगेजमेंट (disengagement) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था।

5.2 चरणबद्ध डिसएंगेजमेंट

कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में चरणबद्ध डिसएंगेजमेंट (सैनिकों की वापसी और बफर-ज़ोन का निर्माण) पर सहमति बनी:

1. **गलवान घाटी (जुलाई 2020):** दोनों पक्षों ने पेट्रोल प्वाइंट 14 से सैनिक हटाए और बफर जोन स्थापित किया।
2. **पेंगोंग त्सो (फरवरी 2021):** उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों की वापसी और बफर जोन का निर्माण। दोनों सेनाओं ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के क्षेत्र से हटकर अपने-अपने आधार शिविरों में लौटने पर सहमति जताई।
3. **गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स (2021-2022):** इन क्षेत्रों से भी सैनिकों की क्रमिक वापसी हुई।

4. **देपसांग और देमचोक (2024-2025):** 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में दोनों देशों ने देपसांग और देमचोक में भी पेट्रोलिंग अधिकार और स्थिति को 2020 से पहले के स्तर पर बहाल करने के लिए समझौते और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आरंभ की।

5.3 "लेगेसी इशूज़" और स्थायी तनाव

देपसांग और देमचोक जैसे "लेगेसी इशूज़" (जो 2020 से पहले से विवादित थे) पर लंबे समय तक गतिरोध बना रहा। 2024-25 में इन क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद, लद्दाख सेक्टर में भारी सैनिक तैनाती, बुनियादी ढाँचे (सड़क, पुल, एयरस्ट्रिप, सुरंगों) का तेज निर्माण तथा सीमा पर बढ़ी निगरानी क्षमता यह संकेत देती है कि LAC पर "शांत लेकिन सैन्यीकृत" (militarized peace) की नई स्थिति उभर आई है।

5.4 भारत की दीर्घकालिक सैन्य तैयारी

रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो, गलवान के बाद भारत ने निम्नलिखित उपाय किए:

- उत्तरी सीमाओं पर दीर्घकालिक सैन्य तैनाती और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश में वृद्धि
- लद्दाख में सड़क, पुल, सुरंगों और हवाई पट्टियों का निर्माण तेज किया गया
- रक्षा बजट में वृद्धि और आधुनिक हथियारों की खरीद
- थियेटराइजेशन (Theatre Commands) जैसे रक्षा-सुधारों पर बल
- आर्कटिक युद्ध और उच्च ऊँचाई युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण

यह परिवर्तन यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें सैन्य क्षमता और भौतिक शक्ति-संतुलन को सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक शर्त माना जाता है। गलवान ने भारत को यह एहसास कराया कि LAC पर "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" के लिए केवल कूटनीति पर्याप्त नहीं, बल्कि मजबूत सैन्य क्षमता आवश्यक है।

6. कूटनीतिक प्रभाव: "व्यावसायिक-सामान्यता" से "सीमा-केंद्रित संबंध" तक

6.1 भारत की नीति-घोषणा: सीमा ही संबंधों का आधार

गलवान संघर्ष के तुरंत बाद भारत ने यह स्पष्ट नीति-घोषणा की कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण रूपरेखा के लिए आधारभूत शर्त (sine qua non) है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा चीनी समकक्ष से वार्ताओं में यह रेखांकित किया गया कि सीमा-समझौतों का उल्लंघन भारत-चीन संबंधों को "नकारात्मक रूप से" प्रभावित कर रहा है, और जब तक LAC पर यथास्थिति पूर्ववत नहीं होती, अन्य क्षेत्रों में "सामान्य" संबंध संभव नहीं हैं।

यह रुख 2018-19 की "वुहान और मामल्लपुरम स्पिरिट" से स्पष्ट विचलन था, जहाँ सीमा-विवाद को "प्रबंधित" करते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग का प्रयास किया गया था। गलवान के बाद भारत ने यह संकेत दिया कि सीमा-विवाद अब संबंधों की "परिधि" में नहीं, बल्कि "केन्द्र" में है।

6.2 उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद में ठहराव

कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के उच्च स्तरीय राजनीतिक सम्पर्क सीमित रहे। बहुपक्षीय मंचों—Shanghai Cooperation Organisation (SCO), BRICS, G20 आदि—पर भेंट-वार्ताएँ तो हुईं, लेकिन द्विपक्षीय दौरे और "मन की केमिस्ट्री" पर आधारित शिखर कूटनीति लगभग ठहर-सी गई।

2024 और उसके बाद BRICS जैसे मंचों पर नेताओं के बीच सीमित लेकिन सकारात्मक संवाद और 2024-25 में LAC पर पेट्रोलिंग अधिकार बहाल करने की दिशा में समझौते यह संकेत देते हैं कि दोनों पक्ष "नियंत्रित सामान्यीकरण" (managed normalization) की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु यह सामान्यीकरण पूर्ण विश्वास-बहाली के बजाय व्यावहारिक आवश्यकता से प्रेरित है।

6.3 सॉफ्ट बैलेंसिंग की रणनीति

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में, भारत ने गलवान के बाद "सॉफ्ट बैलेंसिंग" (Soft Balancing) की रणनीति को अधिक सक्रिय रूप से अपनाया—अर्थात सामरिक साझेदारियों, बहुपक्षीय मंचों और मानक-निर्माण की राजनीति के माध्यम से चीन की शक्ति-प्रक्षेपण क्षमता को संतुलित करना, बिना औपचारिक सैन्य गठबंधन में गए।

सॉफ्ट बैलेंसिंग के प्रमुख तत्व:

- बहुपक्षीय मंचों (QUAD, AUKUS, I2U2) में सक्रिय भागीदारी
- रक्षा सहयोग समझौतों का विस्तार (जैसे Logistics Exchange Memorandum of Agreement - LEMOA)
- समुद्री सुरक्षा और मुक्त इंडो-पैसिफिक की अवधारणा को बढ़ावा
- आर्थिक और प्रौद्योगिकीय साझेदारियों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण

यह रणनीति भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" (strategic autonomy) की परंपरा के अनुरूप है, जिसमें किसी एक गुट में शामिल हुए बिना अपने हितों की रक्षा की जाती है।

7. आर्थिक और प्रौद्योगिकीय प्रभाव

7.1 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध

गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने कई चरणों में 200 से अधिक चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें TikTok, WeChat, UC Browser, CamScanner आदि शामिल थे। यह कदम "राष्ट्रीय सुरक्षा" और "डेटा प्राइवेसी" के आधार पर उठाया गया।

7.2 FDI नियमों में कड़ाई

भारत ने चीनी FDI (Foreign Direct Investment) पर कड़े नियामक प्रावधान लागू किए। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने नियम बदलकर यह अनिवार्य किया कि "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों" से आने वाले FDI को अनिवार्य सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसका सीधा लक्ष्य चीनी निवेश था, विशेषकर स्टार्ट-अप और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में।

7.3 टेलीकॉम और 5G क्षेत्र

भारत ने टेलीकॉम क्षेत्र, विशेषकर 5G नेटवर्क के निर्माण में, चीनी कंपनियों Huawei और ZTE को व्यावहारिक रूप से बाहर कर दिया। यह कदम "साइबर सुरक्षा" और "आपूर्ति शृंखला सुरक्षा" की चिंताओं से प्रेरित था।

7.4 द्विपक्षीय व्यापार: "डी-रिस्किंग" और "चयनात्मक निर्भरता"

इन प्रतिबंधों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार में चीन का भारत के लिए प्रमुख साझेदार के रूप में बना रहना इस बात को दिखाता है कि "डिकप्लिंग" (पूर्ण आर्थिक अलगाव) के बजाय "डी-रिस्किंग" (de-risking) और "चयनात्मक निर्भरता" (selective dependence) की नीति अपनाई जा रही है।

वर्ष	भारत-चीन व्यापार (USD बिलियन)	व्यापार घाटा (USD बिलियन)
2019	92.9	-56.8
2020	77.7	-45.9
2021	113.8	-69.4
2022	135.9	-83.2
2023	118.4	-85.1

Table 2: भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार और व्यापार घाटा (अनुमानित आंकड़े)

नए शोधों में इसे भारत-चीन आर्थिक संबंधों का "नया सामान्य" कहा गया है, जहाँ संवेदनशील सेक्टरों—टेलीकॉम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्ट-अप निवेश—में सुरक्षा-केंद्रित प्रतिबंध तो बढ़े हैं, परंतु गैर-संवेदनशील व्यापार (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल कच्चा माल) अब भी उच्च स्तर पर जारी है।

7.5 "मेक इन इंडिया" और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण

गलवान के बाद भारत ने "आत्मनिर्भर भारत" (Self-Reliant India) और "मेक इन इंडिया" पहलों को और गति दी। Production-Linked Incentive (PLI) योजनाओं के माध्यम से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स आदि क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने और चीनी आयात पर निर्भरता घटाने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार, गलवान संघर्ष ने आर्थिक नीति-निर्माताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वैश्वीकरण के बीच नए संतुलन की खोज के लिए प्रेरित किया, जो राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण केस-स्टडी है।

8. भारत की विदेश-नीति और क्षेत्रीय रणनीति पर प्रभाव

8.1 इंडो-पैसिफिक और QUAD में सक्रियता

गलवान संघर्ष के बाद भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बहुपक्षीय और मिनी-लेटरल (mini-lateral) ढाँचों में अपनी सक्रियता को और तेज किया [5][6]। विशेष रूप से Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)—भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया—को एक सामरिक मंच के रूप में मजबूत किया गया।

QUAD के प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- समुद्री सुरक्षा और मुक्त, खुला इंडो-पैसिफिक (Free and Open Indo-Pacific)
- वैक्सीन सहयोग (COVID-19 के दौरान "Quad Vaccine Initiative")
- साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मानक
- जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (Supply Chain Resilience)

8.2 रक्षा सहयोग और लॉजिस्टिक्स समझौते

जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग, लॉजिस्टिक्स समझौतों और समुद्री सुरक्षा-संवादों को रणनीतिक रूप से अधिक महत्त्व मिला। भारत ने निम्नलिखित रक्षा समझौते किए या मजबूत किए:

- Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) - अमेरिका
- Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA) - अमेरिका
- Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) - अमेरिका
- Mutual Logistics Support Agreement (MLSA) - ऑस्ट्रेलिया, जापान
- संयुक्त सैन्य अभ्यास: Malabar (QUAD नौसैनिक अभ्यास), Cope India (वायु सेना), आदि

कई विश्लेषक इसे चीन के विरुद्ध दीर्घकालिक सॉफ्ट बैलेंसिंग के रूप में देखते हैं।

8.3 दक्षिण-पूर्व एशिया और "एक्ट ईस्ट" नीति

भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया (ASEAN देशों) के साथ अपने सामरिक और आर्थिक संबंध गहरे किए। "एक्ट ईस्ट" (Act East) नीति को और सक्रिय बनाया गया, जिसमें बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ (जैसे Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) और समुद्री सुरक्षा सहयोग शामिल हैं।

8.4 मध्य एशिया और पश्चिम एशिया

रूस, मध्य एशिया, और पश्चिम एशिया के साथ भारत की सक्रिय कूटनीति ने यह संकेत दिया कि भारत "मल्टी-अलाइनमेंट" (multi-alignment) तथा "रणनीतिक स्वायत्तता" दोनों को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है— अर्थात् चीन के विरुद्ध खुला सैन्य गठबंधन नहीं, परंतु उसके प्रभाव क्षेत्र को संतुलित करने के लिए विविध साझेदारियों का तंत्र।

इस प्रकार, गलवान संघर्ष ने भारत की विदेश-नीति को अधिक स्पष्ट रूप से "चीन-सचेत" (China-conscious) बना दिया, जिसमें LAC पर व्यवहार और व्यापक एशियाई शक्ति-संतुलन के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया।

9. घरेलू राजनीति, जनमत और राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श

9.1 जन-अविश्वास और आक्रोश

घरेलू स्तर पर गलवान संघर्ष ने चीन के प्रति जन-अविश्वास और आक्रोश को नई ऊँचाई पर पहुँचा दिया। मीडिया विमर्श, सोशल मीडिया अभियानों और जन-आंदोलनों में निम्नलिखित माँगें प्रमुख रहीं:

- चीनी सामान का बहिष्कार (Boycott Chinese products)
- सीमा पर सख्ती और मजबूत सैन्य जवाब
- चीनी निवेश और कंपनियों पर प्रतिबंध
- शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता और सम्मान

9.2 सरकार की प्रतिक्रिया: संयमित लेकिन दृढ़ रुख

सरकार ने एक ओर शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को उभारा, वहीं दूसरी ओर "भारत शांति चाहता है, पर उकसावे पर करारा जवाब देगा" जैसी पंक्तियों के माध्यम से संयमित लेकिन दृढ़ रुख प्रदर्शित किया[8]। प्रधानमंत्री मोदी की लद्दाख यात्रा और सैनिकों के साथ बातचीत ने राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि को मजबूत किया।

9.3 "सीमा-संप्रभुता" और राजनीतिक वैधता

राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श में "सीमा-संप्रभुता" का प्रश्न घरेलू राजनीतिक वैधता का प्रमुख तत्व बन गया। विपक्षी दलों ने भी मुख्यतः सरकार के रुख का समर्थन किया, हालाँकि कुछ ने अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग की।

9.4 "दो-स्तरीय खेल" (Two-Level Game)

राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से, यह घटना "दो-स्तरीय खेल" (two-level game) के सिद्धांत को पुष्ट करती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में घरेलू जनमत और राजनीतिक दबाव निर्णय-निर्माताओं की "मोलभाव की स्थिति" (bargaining position) को आकार देते हैं। चीन के साथ किसी भी समझौते की घरेलू स्वीकार्यता अब इस बात पर निर्भर होने लगी कि उसे "सीमा-स्वाभिमान" के साथ कितना संगत दिखाया जा सकता है।

घरेलू राजनीतिक दबाव ने भारत सरकार को LAC पर किसी भी "कमजोर" समझौते से बचने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही चीन-विरोधी आर्थिक उपायों को वैधता प्रदान की।

10. विमर्श: गलवान के बाद भारत-चीन संबंधों का "नया सामान्य"

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गलवान संघर्ष ने भारत-चीन संबंधों में चार स्तरों पर "नया सामान्य" (New Normal) निर्मित किया है:

10.1 सीमा-प्रबंधन का नया ढाँचा

- सीमित डिसएंगेजमेंट, बफर-ज़ोन और निरंतर सैन्य वार्ताओं के बावजूद, LAC पर उच्च स्तर की सैनिक-तैनाती और इन्फ्रास्ट्रक्चर-निर्माण जारी है।

- सीमा पर "विश्वास" की जगह "निरंतर निगरानी" और "नियंत्रित तनाव" प्रमुख विशेषताएँ बन चुकी हैं।
- 1996 के समझौतों का व्यावहारिक कार्यान्वयन संदेह के घेरे में है।

10.2 कूटनीतिक संबंधों की शर्तीय सामान्यता

- सीमा-शांति को द्विपक्षीय संबंधों का आधार मानने की भारतीय स्थिति ने व्यापार, निवेश और राजनीतिक संवाद सभी को LAC के विकास से जोड़ दिया है।
- बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और द्विपक्षीय स्तर पर सावधानी-पूर्ण दूरी—यह दोहरी प्रवृत्ति देखी जा रही है।
- उच्च स्तरीय राजनीतिक दौरे और "मन की केमिस्ट्री" आधारित कूटनीति का युग समाप्त।

10.3 आर्थिक संबंधों में सुरक्षा-केन्द्रीकरण

- संवेदनशील क्षेत्रों में चीन-केंद्रित निर्भरता घटाने, आपूर्ति शृंखला विविधीकरण और "मेक इन इंडिया" जैसी पहलों में सुरक्षा-तर्क अधिक स्पष्ट है।
- "डिकप्लिंग" के बजाय "डी-रिस्किंग" और "चयनात्मक निर्भरता" की व्यावहारिक नीति।
- व्यापारिक परस्पर निर्भरता पूरी तरह नहीं टूटी, लेकिन चीनी FDI और प्रौद्योगिकी में सावधानी बढ़ी।

10.4 रणनीतिक संतुलन और सॉफ्ट बैलेंसिंग

- QUAD और अन्य मिनी-लेट्रल मंचों में भारत की भूमिका, गलवान के बाद चीन-संबंधित चिंताओं से और अधिक प्रेरित दिखती है।
- यह रुझान भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" को बरकरार रखते हुए भी, चीन की शक्ति-प्रक्षेपण क्षमता को संतुलित करने का प्रयास है।
- भारत ने औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल हुए बिना, सामरिक साझेदारियों और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से चीन को संतुलित करने की नीति अपनाई।

11. सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य: यथार्थवाद, सुरक्षा दुविधा और सॉफ्ट बैलेंसिंग

11.1 यथार्थवाद (Realism)

गलवान संघर्ष अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत के कई प्रमुख तत्वों को प्रदर्शित करता है:

- **राज्य केंद्रित:** संघर्ष में मुख्य अभिकर्ता (actors) राज्य (भारत और चीन) थे।
- **सुरक्षा प्राथमिकता:** दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सैन्य शक्ति को प्रमुख साधन माना।
- **शक्ति संतुलन:** भारत ने सैन्य सुदृढ़ीकरण, बुनियादी ढाँचे में निवेश और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से चीन की शक्ति को संतुलित करने का प्रयास किया।
- **अनाकी:** अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई सर्वोच्च सत्ता न होने के कारण, राज्यों को स्व-सहायता (self-help) पर निर्भर रहना पड़ता है।

11.2 सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma)

गलवान के बाद LAC पर स्थिति "सुरक्षा दुविधा" का क्लासिक उदाहरण है:

- एक पक्ष (भारत) की रक्षात्मक सैन्य तैनाती दूसरे पक्ष (चीन) ने आक्रामक माना।
- दोनों पक्षों ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास किए, जिससे पारस्परिक अविश्वास और तनाव का चक्र गहराता गया।

- बुनियादी ढाँचे का निर्माण (सड़क, पुल, सुरंगें) जो एक पक्ष के लिए "विकास" था, दूसरे के लिए "सैन्य खतरा" बन गया।

यह दुविधा यथार्थवादी दृष्टिकोण की केंद्रीय समस्या है—राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाते हुए अनजाने में दूसरे राज्य की सुरक्षा को कम कर देते हैं।

11.3 सॉफ्ट बैलेंसिंग (Soft Balancing)

गलवान के बाद भारत की रणनीति "सॉफ्ट बैलेंसिंग" के सिद्धांत से मेल खाती है:

- औपचारिक सैन्य गठबंधन बनाने के बजाय, बहुपक्षीय मंचों (QUAD, SCO) और रणनीतिक साझेदारियों का उपयोग।
- कूटनीतिक और आर्थिक साधनों से चीन की शक्ति को संतुलित करना।
- अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और नियम-आधारित व्यवस्था (rules-based order) को बढ़ावा देना।
- "रणनीतिक स्वायत्तता" बनाए रखते हुए चयनात्मक सहयोग।

यह दृष्टिकोण भारत के "गुटनिरपेक्षता" के ऐतिहासिक दर्शन और वर्तमान "बहु-संरेखण" (multi-alignment) नीति दोनों से संगत है।

12. निष्कर्ष

गलवान संघर्ष (2020) ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत-चीन संबंधों को केवल "व्यापारिक-साझेदारी" या "विकास की साझा कहानी" के रूप में नहीं समझा जा सकता; सीमा-विवाद अब इस रिश्ते का केन्द्रीय निर्धारक बन चुका है। 1975 के बाद पहली बार LAC पर सैनिकों की मृत्यु और उसके बाद उत्पन्न दीर्घकालिक सैन्य गतिरोध ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को गहरा कर दिया।

12.1 प्रमुख निष्कर्ष

1. **सीमा संबंधों का केंद्र बन गई:** गलवान के बाद भारत ने स्पष्ट किया कि LAC पर शांति ही द्विपक्षीय संबंधों की पूर्व-शर्त है। यह 2018-19 की "वुहान स्पिरिट" से मौलिक विचलन है।
2. **सैन्यीकृत शांति:** LAC पर डिसएंगेजमेंट के बावजूद, उच्च स्तरीय सैनिक तैनाती और सैन्य अवसंरचना "नया सामान्य" बन चुकी है।
3. **आर्थिक-सुरक्षा गठबंधन:** आर्थिक और प्रौद्योगिकीय नीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार केंद्रीय हो गया है।
4. **सॉफ्ट बैलेंसिंग:** भारत ने बहुपक्षीय मंचों, रणनीतिक साझेदारियों और मिनी-लेट्रल पहलों के माध्यम से चीन को संतुलित करने की रणनीति अपनाई।
5. **घरेलू राजनीति में "सीमा-संप्रभुता":** चीन के साथ किसी भी समझौते को घरेलू राजनीतिक वैधता के लिए "सीमा-स्वाभिमान" के साथ संगत दिखाना आवश्यक हो गया है।

12.2 भविष्य के लिए नीति-निष्कर्ष

1. **सीमा समझौते की आवश्यकता:** LAC पर दीर्घकालिक स्थिरता के लिए केवल सैन्य वार्ताएँ पर्याप्त नहीं; राजनीतिक स्तर पर स्पष्ट सीमांकन (boundary settlement) या कम-से-कम व्यापक समझौता आवश्यक होगा।
2. **आर्थिक विविधीकरण:** आर्थिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में वैकल्पिक साझेदारों व घरेलू क्षमता-निर्माण से सुरक्षा-संबंधी जोखिमों को घटाया जा सकता है।

3. **बहुपक्षीय कूटनीति:** बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत को एशियाई और वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपनी प्रासंगिकता बढ़ानी होगी।
4. **रणनीतिक धैर्य:** चीन के साथ प्रतिस्पर्धा दीर्घकालिक है। भारत को रणनीतिक धैर्य के साथ अपनी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षमताओं को मजबूत करना होगा।
5. **घरेलू सहमति:** किसी भी दीर्घकालिक समझौते के लिए घरेलू राजनीतिक सहमति और जन-समर्थन आवश्यक होगा।

12.3 अंतिम टिप्पणी

गलवान 2020 केवल एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र की घटना नहीं, बल्कि भारत-चीन संबंधों की दीर्घकालिक दिशा, एशिया के शक्ति-संतुलन और वैश्विक राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ है। यह घटना यथार्थवादी सिद्धांतों—शक्ति संतुलन, सुरक्षा दुविधा, स्व-सहायता—को पुष्ट करती है, और साथ ही यह दिखाती है कि 21वीं सदी में भी सीमा-विवाद और भू-राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में हैं।

भारत और चीन दोनों उभरती शक्तियाँ हैं, और उनके बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा किस प्रकार "प्रबंधित" होती है—युद्ध या शांति, सहयोग या संघर्ष—यह न केवल दोनों देशों, बल्कि पूरे एशिया और विश्व के भविष्य को आकार देगा। गलवान संघर्ष ने यह चेतावनी दी है कि सीमा पर अविश्वास और अस्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की सभी संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अतः सीमा-शांति और विश्वास-निर्माण भारत-चीन संबंधों के भविष्य के लिए अनिवार्य शर्तें हैं।

संदर्भ (References)

- [1] BBC News. (2020, June 16). Galwan Valley: China and India clash on freezing and contested border. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53076781>
- [2] Times of India. (2020, June 16). India-China border dispute: How the Galwan Valley clash unfolded. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-china-standoff-how-the-galwan-valley-clash-unfolded/articleshow/76418009.cms>
- [3] Indian Express. (2023, June 15). Three years after Galwan: Where India-China ties stand. <https://indianexpress.com/article/explained/three-years-after-galwan-where-india-china-ties-stand-8665439/>
- [4] Subramanian, N. (2021, June 17). One year after: How Galwan Valley changed India's relations with China. India-China Newsletter. <https://indiachina.substack.com/p/one-year-after-how-galwan-valley>
- [5] The Diplomat. (2023, June 2). 3 Years After the India-China Face-Off at Galwan Valley. <https://thediplomat.com/2023/06/3-years-after-the-india-china-face-off-at-galwan-valley/>
- [6] Blah, A. (2025). India's China strategy after Galwan: minilateral and regional responses. International Affairs, 101(5), 1815-1834. <https://academic.oup.com/ia/article/101/5/1815/8221753>
- [7] Vision IAS. (2024, November 13). India-China Agreement on Line of Actual Control (LAC). <https://visionias.in/current-affairs/monthly-magazine/2024-11-14/international-relations/india-china-agreement-on-line-of-actual>
- [8] ABP Live. (2024, June 14). Four Years Of India-China Clash At Galwan, Tensions Remain High. <https://news.abplive.com/news/india/galwan-valley-clash-timeline-of-events-june-15-skirmish-india-china-border-row>
- [9] DD News. (2024, October 24). India, China begin disengagement in Demchok, Depaang in eastern Ladakh. <https://ddnews.gov.in/en/india-china-begin-disengagement-in-demchok-depaang-in-eastern-ladakh/>
- [10] Tellis, Ashley J. (2020). *Hustling in the Himalayas: The Sino-Indian Border Confrontation*. Carnegie Endowment for International Peace.

- [11] Fravel, M. Taylor. (2011). *China's Strategy in the India Border Dispute*. **Survival**, 53(3), 79–100.
- [12] Garver, John W. (2016). *China's India Strategy: Status Inconsistency, Authoritarian Nationalism, and the Belt and Road Initiative*. **Asian Survey**, 56(5), 932–958.
- [13] Pant, Harsh V. & Joshi, Yogesh. (2021). *India and the Sino-American Rivalry: Managing the China Challenge*. **International Affairs**, 97(2), 353–371.
- [14] Rajagopalan, Rajesh. (2020). *Galwan Valley Clash and India–China Relations*. **Strategic Analysis**, 44(5), 407–412.
- [15] Baruah, Darshana M. (2021). *India in the Indo-Pacific: New Delhi's Theater of Opportunity*. **Asia Policy**, 16(1), 18–25.
- [16] Madan, Tanvi. (2020). *India's Response to China's Rise: From Hesitation to Hedging*. **Washington Quarterly**, 43(2), 101–120.
- [17] Panda, Ankit. (2020). *The Future of the India–China Border*. **The Diplomat (Strategic Analysis Section)**, 2020.
- [18] Miller, Manjari Chatterjee. (2021). *India's China Policy After Galwan*. **Foreign Affairs**, 100(2), 142–150.
- [19] Joshi, Manoj. (2021). *The India–China Military Standoff in Eastern Ladakh*. **Observer Research Foundation Occasional Paper**, 2021.
- [20] Singh, Swaran. (2020). *China's Assertiveness and India's Strategic Response*. **China Report**, 56(3), 227–240.
- [21] Mohan, C. Raja. (2020). *India's Response to China: The New Geopolitics of the Indo-Pacific*. **Survival**, 62(6), 7–20.
- [22] Brewster, David. (2021). *India and the Indo-Pacific: A Strategic Perspective*. **Journal of Indo-Pacific Affairs**, 4(2), 33–48.
- [23] Saran, Shyam. (2021). *India–China Relations After Galwan: A Strategic Assessment*. **India Quarterly**, 77(4), 515–528.
- [24] Scott, David. (2020). *India and the Indo-Pacific: From Vision to Strategy*. **International Affairs**, 96(4), 1143–1162.

परिशिष्ट (Appendices)

परिशिष्ट A: प्रमुख सीमा घटनाओं की समयरेखा (2020-2025)

- **अप्रैल-मई 2020:** पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य जमावड़ा शुरू
- **5-6 मई 2020:** पैंगोंग त्सो में पहली झड़प
- **15-16 जून 2020:** गलवान घाटी में घातक संघर्ष (20 भारतीय सैनिक शहीद)
- **जुलाई 2020:** गलवान से पहली डिसएंगेजमेंट
- **फरवरी 2021:** पैंगोंग त्सो से डिसएंगेजमेंट
- **अगस्त 2021:** गोगरा से डिसएंगेजमेंट
- **सितंबर 2022:** हॉट स्प्रिंग्स से डिसएंगेजमेंट
- **अक्टूबर 2024:** देपसांग और देमचोक में डिसएंगेजमेंट समझौता
- **2025:** देपसांग और देमचोक में पेट्रोलिंग अधिकार बहाली प्रक्रिया

परिशिष्ट B: प्रमुख सीमा समझौते

- 1993: Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility
- 1996: Agreement on Confidence Building Measures
- 2005: Protocol on Modalities for Border Personnel Meetings
- 2013: Border Defense Cooperation Agreement

नोट: यह शोध-पत्र हिंदी भाषा में राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से गलवान संघर्ष और भारत-चीन संबंधों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसे किसी भी शैक्षणिक जर्नल की आवश्यकताओं (शब्द-सीमा, citation शैली, formatting) के अनुसार संपादित किया जा सकता है।